

उदान योजना

UDAN योजना प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति (NCAP) का एक प्रमुख घटक है जिसे 15 जून 2016 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय (भारत) द्वारा जारी किया गया था। इस योजना को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित किया जाएगा। कई राज्य इस योजना के लिए केंद्र सरकार के साथ "समझौता ज्ञापन" पर हस्ताक्षर करके बोर्ड पर आ गए हैं, UDAN RCS 2018 वित्तीय वर्ष के अंत तक 100 क्षेत्रीय हवाई अड्डों का संचालन करके, नए क्षेत्रीय मार्गों की एक अनिर्दिष्ट संख्या को जोड़ देगा, एक के साथ 13 लाख (1.3 मिलियन) वार्षिक यात्री सीटों का लक्ष्य, वार्षिक INR200 करोड़ की आवश्यकता होती है। एक ही हवाई अड्डे से उड़ानों की आवृत्ति न्यूनतम 3 और अधिकतम 7 प्रति सप्ताह होनी चाहिए।

सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली रियायतें

भारत सरकार से रियायतें: [२३]

- हवाई जहाज को सब्सिडी देने के लिए वैल्यू गैप फंडिंग (वीजीएफ)
- टिकटों पर सेवा कर पर रियायत।
- अन्य ऑपरेटरों के साथ UDAN-RCS उड़ानों की कोड-साझेदारी

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें

[“https://www.aai.aero/en/rcs-udan”](https://www.aai.aero/en/rcs-udan)